मैंने कांग्रेस आलाकमान के कहने पर दिया त्यागपत्र : सिद्दरमैया

लोकभवन जाकर राज्यपाल के विशेष सचिव को सौंपा त्यागपत्र, डीके शिवकुमार का रास्ता साफ

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान खत्म हो गई। कांग्रेस नेता सिद्दरमैया ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही कहा, आलाकमान ने उनसे जो कहा, उन्होंने किया। वर्तमान में उपमुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस्तीफा देने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट सहयोगियों के लिए आयोजित नाश्ते पर शिवकुमार ने सिद्दरमैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया।

कांग्रेस हाईकमान ने सिद्दरमैया को राज्यसभा की सदस्यता का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इसे उन्होंने ठुकरा दिया और कहा कि वह प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहते हैं। बेंगलुरु में घटनाक्रम के बाद दोनों नेता मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया के लिए पार्टी हाईकमान से मिलने अलग-अलग दिल्ली रवाना हो गए।

राज्यपाल थावरचंद गहलोत के राज्य से बाहर होने के कारण लोकभवन में राज्यपाल के विशेष सचिव प्रभु शंकर को इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्दरमैया ने प्रेस से बात की। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री और संभावित उत्तराधिकारी शिवकुमार और कैबिनेट के अन्य सहयोगी भी उपस्थित थे। 77 वर्षीय सिद्दरमैया ने विश्वास जताया कि राज्यपाल संवैधानिक प्रविधानों के अनुसार उनका इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे।

दो दिनों में साफ होगी स्थिति

पार्टी सूत्रों के अनुसार, दिल्ली प्रवास के दौरान दोनों नेताओं की आलाकमान के साथ विधायक दल के नए नेता के चयन, मंत्रिमंडल की संरचना और अन्य तौर-तरीकों पर चर्चा होने की संभावना है। अन्य मुद्दों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी शामिल है, जो वर्तमान में शिवकुमार के पास है। सूत्रों ने कहा कि इन सभी मामलों पर एक-दो दिनों में स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

शिवकुमार के घर जश्न

सिद्दरमैया के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने राज्य के विरोध प्रदर्शन किए। उनके आवास पर भी भावुक दृश्य देखने को मिले, जब समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और इस्तीफा नहीं देने का आग्रह किया। शिवकुमार के अगला सीएम बनने के संकेतों के बाद उनके आवास के पास जश्न का माहौल देखा गया। कांग्रेस के कई नेताओं और विधायकों ने शिवकुमार के आवास पर जाकर उन्हें बधाई दी।

विधानसभा चुनाव के बाद से थी सीएम पद के लिए खींचतान

मई, 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्दरमैया और शिवकुमार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। तब पार्टी ने शिवकुमार को मनाकर उपमुख्यमंत्री बना दिया था। उस समय बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनने की व्यवस्था पर सहमति की चर्चा थी, लेकिन पार्टी या दोनों नेताओं ने इस संबंध में पुष्टि नहीं की थी। सूत्रों ने बताया कि सिद्दरमैया ने पद छोड़ने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि यह संदेश सीधे पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी की ओर से आया था। पार्टी ने मंगलवार को सिद्दरमैया और शिवकुमार को दिल्ली बुलाया था।

बेंगलुरु में गुरुवार को बैठक के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के पैर छूते उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। एएनआइ

खेती को अलनीनो संकट से बचाने की केंद्र ने तेज की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बदलते मौसम और अलनीनो के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों को लेकर तैयारी तेज कर दी है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन में मौसम से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक और व्यावहारिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्र सरकार का स्पष्ट संदेश है कि मौसम की अनिश्चितता से घबराने के बजाय पहले से तैयारी करनी होगी, ताकि किसानों और फसलों के उत्पादन पर असर कम से कम पड़े।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि जिन जिलों में अलनीनो का असर पड़ने की आशंका है, वहां वैकल्पिक फसलों की पहचान, बीज उपलब्धता और फसल परिवर्तन की अग्रिम योजना तैयार की जा रही है। खरीफ सीजन में राज्यों को समय पर बीज और तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सम्मेलन में केंद्र व राज्यों के कृषि मंत्री, आइसीएआर के विज्ञानी, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ,

- **खरीफ सम्मेलन में मौसम की चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा**
- **अलनीनो से घबराने के बजाय वैकल्पिक फसल और बीज योजना पर जोर**

नई दिल्ली में गुरुवार को बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आइएएनएस

एफपीओ प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस दौरान खरीफ फसलों की रणनीति, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक खेती, डिजिटल कृषि, बीज गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने जैसे मुद्दों पर व्यापक मंथन हुआ।

विशेषज्ञों ने कहा कि लगातार बढ़ती गर्मी, अनियमित बारिश और लंबे सूखे अंतराल खेती की परिस्थितियों को तेजी से बदल रहे हैं। इसी वजह से प्राकृतिक खेती, स्वाइल हेल्थ कार्ड और उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर विशेष फोकस किया गया। कई जिलों में जरूरत से अधिक उर्वरक उपयोग को चिंता का विषय बताया गया।

छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग माडल पर भी जोर दिया गया। सरकार का मानना है कि कम जमीन वाले किसान खेती के साथ पशुपालन, बागवानी और दूसरी गतिविधियों को जोड़कर अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। कृषि ऋण वितरण में राज्यों के बीच असमानता दूर करने, किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज बढ़ाने और किसानों को निवेश के लिए पूंजी उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई।

सरकार ने इस बार दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। अलग-अलग मिशनों के माध्यम से बेहतर बीज, सीड रिप्लेसमेंट रेट बढ़ाने, खेतों में प्रदर्शन कार्यक्रम और प्रोसेसिंग ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। आइसीएआर महानिदेशक एमएल जाट ने कहा कि चावल के कुछ क्षेत्र को अब दलहन और तिलहन की ओर मोड़ने की जरूरत है, ताकि इन फसलों में आत्मनिर्भरता पाई जा सके।

खरीफ सम्मेलन से गैरहाजिर मंत्रियों पर शिवराज सख्त

खरीफ सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कुछ राज्यों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं थे, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता है तो उसे पद पर बने रहने का अधिकार भी नहीं है। उनका यह बयान किसानों से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय करने का बड़ा संकेत माना जा रहा है। दो दिवसीय सम्मेलन में खरीफ फसलों की तैयारी और किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा के लिए राज्यों के कृषि मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया है। मंत्रियों से विमर्श शुक्रवार को होना है, लेकिन कई राज्यों के कृषि मंत्रियों के आने की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सम्मेलन में शिवराज अलग कार्यशैली में नजर आए। वह सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहे। पीछे बैठकर विशेषज्ञों की बात ध्यान से सुनते रहे और जरूरी नोट्स भी लेते दिखाई दिए।

गजेंद्र सिंह

लोक नीति विश्लेषक

आजकल

संतुलित और टिकाऊ कृषि नीति की जरूरत

भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की लगभग 50 प्रतिशत कार्यशील आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है, जबकि कृषि का योगदान भारत की जीडीपी में 15-17 प्रतिशत ही है। यह विरोधाभास स्वयं संकेत देता है कि देश की आधी जनसंख्या जिस क्षेत्र पर निर्भर है, उसकी आय और उत्पादकता अपेक्षाकृत कम बनी हुई है। इसके बावजूद भारतीय कृषि आज कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है- घटती उत्पादकता, जल संकट, फसल असंतुलन, बढ़ती आयात निर्भरता और किसानों की आय का संकट। लिहाजा इनसे निपटने की जरूरत है

धान की खेती में बहुत अधिक पानी की खपत होती है, लिहाजा खेती के चक्र में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। फाइल

एक समय भारत खाद्य आत्मनिर्भरता और कृषि निर्यात के लिए विश्व में उदाहरण माना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में कृषि व्यापार की तस्वीर तेजी से बदली है। वर्ष 2013-14 में भारत का कृषि निर्यात, कृषि आयात की तुलना में लगभग 27 अरब डालर अधिक था। उस समय कृषि आयात लगभग 15.5 अरब डालर और निर्यात लगभग 43.3 अरब डालर का था। लेकिन वर्ष 2025-26 तक यह अंतर घटकर लगभग 12.7 अरब डालर रह गया है। इस अवधि में कृषि आयात बढ़कर लगभग 40.4 अरब डालर तक पहुंच गया, जबकि कृषि निर्यात लगभग 53.1 अरब डालर रहा। ये आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था आयात आधारित होती जा रही है। विशेष चिंता की बात यह है कि भारत उन वस्तुओं का भी बड़े पैमाने पर आयात कर रहा है, जिनका उत्पादन देश के किसान स्वयं कर सकते हैं।

भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देशों में शामिल है। देश अपनी कुल खाद्य तेल आवश्यकता का लगभग 55-60 प्रतिशत आयात करता है। वर्ष 2025-26 में भारत ने लगभग 169.4 लाख टन खाद्य तेल आयात किया, जिसकी कुल कीमत लगभग 19.5 अरब डालर रही। इसी अवधि में भारत ने लगभग 59.6 लाख टन दालों का आयात किया, जिसकी कीमत लगभग 3.6 अरब डालर रही। अरहर, मसूर, मटर और उड़द जैसी दालें मुख्यतः कनाडा, आस्ट्रेलिया, म्यांमार और रूस से खरीदी गईं। इसके अलावा, भारत ने लगभग 3.5 अरब डालर मूल्य के ताजे फलों का आयात किया। एक समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक रहा भारत अब रिकार्ड स्तर पर कच्चा कपास आयात कर रहा है। यह स्थिति एक कृषि प्रधान देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि जिन वस्तुओं का उत्पादन देश के किसान स्वयं कर सकते हैं, उनके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है।

वहीं भारत के कृषि निर्यात के आंकड़े इस प्रकार हैं। वर्ष 2025-26 में भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक रहा, जिसमें बासमती चावल का निर्यात लगभग 5.8 अरब डालर और गैर-बासमती चावल का निर्यात लगभग 4.4 अरब डालर रहा। इसी अवधि में भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात लगभग 8.4 अरब डालर तक पहुंचा, जबकि मिर्च, जीरा, हल्दी, इलायची और धनिया जैसे मसालों का निर्यात चार अरब डालर से अधिक रहा।

भारत की कृषि नीति लंबे समय तक गेहूं और धान केंद्रित रही है। हरित क्रांति के बाद पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में धान और गेहूं उत्पादन को भारी प्रोत्साहन दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकारी खरीद और मुफ्त या सस्ती बिजली जैसी नीतियों ने किसानों को इन्हीं फसलों पर निर्भर बना दिया। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम भूजल संकट के रूप में सामने आया। नीति आयोग की रिपोर्टों के अनुसार भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और देश के कई कृषि क्षेत्र "डार्क जोन" की श्रेणी में पहुंच चुके हैं।

सरकारी प्रयास : सरकार ने आगामी खरीफ सीजन की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करते हुए दलहन, तिलहन और कपास जैसी फसलों पर अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि की है, जबकि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल तीन प्रतिशत वृद्धि की गई है। किसानों को पारंपरिक जल-गहन फसलों से हटाकर फसल विविधीकरण की ओर प्रोत्साहित करना है, ताकि खाद्य तेल और दालों में बढ़ती आयात निर्भरता को कम किया जा सके। इसी दिशा में सरकार ने खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन, आयल पाम मिशन और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं, जिनका लक्ष्य घरेलू उत्पादन बढ़ाना, किसानों की आय में सुधार करना और कृषि क्षेत्र को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाना है।

हालांकि केवल एमएसपी बढ़ा देना अथवा नई योजनाओं और मिशनों की घोषणा कर देना ही पर्याप्त समाधान नहीं होगा। दलहन और तिलहन जैसी फसलें मौसम, कीट, रोग और पाले से जल्दी प्रभावित होती हैं तथा कई बार बाजार में इनके दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चले जाते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यही कारण है कि किसान गेहूं और धान जैसी अपेक्षाकृत सुरक्षित फसलों से बाहर निकलने में संकोच करते हैं। ऐसे में फसल विविधीकरण को सफल बनाने के लिए मजबूत फसल बीमा, सरकारी खरीद की गारंटी, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, प्रसंस्करण उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन, कृषि अनुसंधान और बेहतर बीज विकास जैसे व्यापक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता होगी। कृषि क्षेत्र में नवाचार और कृषि उद्यमिता से जुड़ी निधियों का बड़ा हिस्सा सीधे किसानों तक पहुंचना चाहिए।

भारत की कृषि नीति लंबे समय तक 'अधिक उत्पादन' केंद्रित रही है, लेकिन अब आवश्यकता 'संतुलित और टिकाऊ कृषि व्यवस्था' की है, जिसमें जल संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता, पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और आयात निर्भरता जैसे सभी पहलुओं को साथ लेकर चलना होगा। भारत के सामने चुनौती केवल उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि 'सही फसल, सही क्षेत्र और सही नीति' तय करने की है। यदि किसानों की स्थायी आय और जल सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, तो कृषि नीति को अल्पकालिक राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाकर दीर्घकालिक राष्ट्रीय रणनीति के रूप में पुनर्गठित करना होगा।

बासमती धान उत्पादकों को मिले राहत

डा. वीरेंद्र सिंह लाठर

पूर्व प्रधान विज्ञानी, आइएआरआई, नई दिल्ली

वर्तमान में सरकार केवल सामान्य धान और ग्रेड-ए धान के लिए ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। वर्ष 2026-27 के लिए इसे क्रमशः 2,441 व 2,461 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। लेकिन सरकार द्वारा बासमती धान की एमएसपी घोषित नहीं करने से बासमती धान उत्पादक किसानों को बिचौलिए साहूकार और धान मिल मालिकों के रहमोकरम पर छोड़ रखा है।

उल्लेखनीय है कि भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का अग्रणी निर्यातक है। देश ने वर्ष 2024-25 के दौरान 50,312 करोड़ रुपये मूल्य का बासमती चावल विश्व को निर्यात किया है। एपीईडीए (एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी) ने विदेशी व्यापार समझौते के दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत से बासमती चावल के सदस्य निर्यातकों के लिए 43,262 पंजीकरण सह आवंटन प्रमाण पत्र (आरसीएसी) जारी किए हैं। बासमती चावल का निर्यात औसत 9300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किया गया। देश के घरेलू बाजार में भी बासमती चावल का औसत बाजार मूल्य 10 हजार रुपये प्रति क्विंटल से अधिक ही रहता है। इसके बावजूद, बिचौलियों और राइस मिलर्स के भ्रष्ट कार्टेल किसानों से बासमती धान की खरीद मात्र 1500- 3500 रुपये (औसत 2,700 रुपये) प्रति क्विंटल दाम पर करके किसानों का खुला शोषण करते हैं। जबकि वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार एक क्विंटल बासमती धान से लगभग 67 किलो चावल मिलता है, यानी बासमती चावल के विपणन का 60 प्रतिशत से अधिक लाभ बिचौलियों, राइस मिलर्स और व्यापारी हड़प जाते हैं। जबकि बासमती धान की खेती करने वाले किसान को 35 हजार रुपये प्रति एकड़ से अधिक भारी-भरकम लागत लगाने और खरीफ मानसून वर्षा सीजन की प्राकृतिक आपदा से जूझने के बावजूद नाममात्र लाभ और बहुत बार ऋणात्मक लाभ ही मिलता है। केंद्रीय कृषि मूल्य एवं लागत आयोग के अनुसार, वर्ष 2025 में धान खेती की व्यापक लागत 2090 रुपये प्रति क्विंटल है। इसलिए 2,100 रुपये प्रति क्विंटल में बिकने वाली बासमती किसानों के लिए घाटे का सौदा है।

किसानों, बिचौलियों और राइस मिलर्स के लालच से बासमती चावल की गुणवत्ता पर गहरा संकट बना हुआ है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से बासमती धान की खेती निर्धारित भौगोलिक संकेत (जीआइ) क्षेत्र से बाहर के राज्यों में भी बड़े स्तर होने लगी है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन बासमती धान पर प्रतिबंध नहीं होने और आलू उत्पादक किसानों द्वारा अगेती बासमती फसल लगाने से पूसा बासमती-1509 जैसी कम अवधि वाली किस्में अगस्त में ही मंडियों में बिक्री के लिए आ जाती हैं। इस फसल को अवैध लाभ बढ़ाने के लिए राइस मिलर्स औने-पौने दाम पर खरीदकर बासमती चावल में मिलावट करके इसकी गुणवत्ता को कम कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, बिचौलियों और राइस मिलर्स मंडियों में भ्रष्ट कार्टेल बनाकर बासमती धान के खरीद दाम में भारी हेराफेरी करके वर्षों से किसानों को खुला शोषण करते रहे हैं। इसीलिए बासमती धान खेती की आर्थिक व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए सरकार को सामान्य धान के मुकाबले डेढ़ गुणा अधिक एमएसपी दाम घोषित करके, बासमती धान को एमएसपी विपणन प्रणाली में लाना चाहिए, जिससे किसानों की बिचौलियों और राइस मिलर्स द्वारा वर्षों से की जा रही खुली लूट पर रोक लगाने और बासमती के दाम में अनिश्चितता को खत्म किया जा सकेगा। इससे किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सकेगा और बासमती चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी।

Power shift in Karnataka as Siddaramaiah resigns

Two-time Chief Minister points at his deputy Shivakumar as successor after stepping down from the post; not interested in national politics, will fight communal forces till last breath, he declares

Sharath S. Srivatsa
BENGALURU

Two-time Karnataka Chief Minister Siddaramaiah tendered his resignation on Thursday, paving the way for transition of power to his deputy D.K. Shivakumar. The formation of the next government is likely to be discussed in Delhi on Friday.

After visiting the Lok Bhavan to hand over his resignation to the Special Secretary to Governor Thaawarchand Gehlot, who was away in Indore, Mr. Siddaramaiah proceeded to Delhi for talks with the Congress central leadership over the formation of the next government.

However, his flight was diverted to Jaipur owing to bad weather on Thursday night. Mr. Shivakumar also left for Delhi.

Rein change: Siddaramaiah leaves after a press meet in Bengaluru on Thursday. D.K. Shivakumar is also seen. SUDHAKARA JAIN

Though the Congress is yet to formally name his successor, Mr. Siddaramaiah, during a media conference, pointed to Mr. Shivakumar as the next Chief Minister. There has also been no official word on the Congress Legislature Party meeting, although speculation is rife that it could take place on Friday evening.

"I have stood down after the high command asked me to do so. I will remain in active politics and fight communal forces till my last breath. The high command asked me to go to the Rajya Sabha. But with humility, I have told them that I am not interested in national politics," said Mr. Siddaramaiah, who entered politics in the local body elections in 1978. "I owe my career to the Constitution drafted by the committee chaired by B.R. Ambedkar."

Mr. Siddaramaiah, the State's longest serving Chief Minister, said he would serve the remaining two years as a legislator.

The announcement brings to an end the speculation over leadership that has plagued the government for nearly a year and is expected to end public posturing by both factions.

CONTINUED ON
» **PAGE 12**
MORE REPORTS ON
» **PAGES 5 & 13**

Will increasing the strength of the SC solve the pendency problem?

Prashant Reddy T.

Legal Academic and co-author of 'Tareekh Pe Justice: Reforms for India's District Courts'

Swapnil Tripathi

leads Chakra, the constitutional law centre at Vidhi Centre for Legal Policy

PARLEY

On May 17, the President promulgated an ordinance increasing the sanctioned strength of the Supreme Court from 34 to 38 judges. The move came just days after the Union Cabinet approved the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026, stating that the addition of four judges would enable the top court to facilitate "speedy justice". On May 27, the Supreme Court Collegium recommended the elevation of four High Court Chief Justices and senior advocate V. Mohana as judges of the top court. According to the National Judicial Data Grid, pendency before the SC currently stands at 93,966 cases. Is increasing the top court's strength an effective way to reduce pendency? Prashant Reddy T. and Swapnil Tripathi discuss the question in a conversation moderated by **Aaratrika Bhaumik**.

Was the ordinance route necessary to increase the top court's sanctioned strength?

Prashant Reddy: No. With Parliament set to convene within weeks, the government could easily have introduced the proposal through the ordinary legislative process. In any event, previous Bills increasing the sanctioned strength of the top court have often passed with minimal debate. In fact, in 2009, the government reportedly introduced a similar measure through a money Bill owing to its numerical disadvantage in the Rajya Sabha. Resorting to an ordinance for a measure of this nature deepens institutional scepticism and fuels unnecessary speculation about the motives of the move.

Does the Supreme Court's willingness to entertain a large number of Special Leave Petitions (SLPs) contribute to the pendency?

Swapnil Tripathi: Yes. The Constituent Assembly envisaged that the Supreme Court would exercise considerable restraint, particularly in invoking its extraordinary jurisdiction under Article 136 of the Constitution. SLPs were conceived as a remedy to be exercised sparingly. Over time, however, a substantial portion of the Supreme Court's docket has come to be dominated by SLPs. What is even more concerning is the court's persistent reluctance to formulate clear guidelines governing the exercise of this jurisdiction. The absence of any meaningful guidelines has contributed to the very accumulation of arrears the institution is now struggling to manage.

PR: The difficulty with Article 136 is that there has never been a clear consensus, even within

The Supreme Court of India.

the Constituent Assembly, on the precise role this jurisdiction was intended to perform. In most other common law jurisdictions, top courts have evolved institutional filters to regulate discretionary appeals, mindful of the finite judicial time available to them. They generally confine themselves to the most contentious or jurisprudentially significant cases. By contrast, as recently as 2016, a Constitution Bench of the Supreme Court declined to narrow the scope of Article 136, observing that no effort should be made to restrict the court's powers under the provision. The result is an increasingly unpredictable system in which outcomes often appear contingent on the Bench before which a matter is listed. This, in turn, fuels allegations of Bench fixing and corrupt listing practices, eroding the court's legitimacy in the eyes of the public.

Should the Court confine itself primarily to constitutional cases to reduce backlog?

PR: No. Last year, in *Vijaya Bank & Anr. versus Prashant B. Narnaware*, a Division Bench of the Supreme Court was called upon to interpret Section 27 of the Indian Contract Act. The case was about the validity of a bond clause; allowing a public sector bank to recover damages from an employee who resigned before completing a mandatory three-year service period. Although framed as a contract law dispute, the issue went to the heart of the right to work and carried significant implications for labour mobility and market competition. Questions of law with such far-reaching consequences must engage the top court's attention. The real concern is not that the Court hears such cases, but how it hears them. Matters involving substantial questions of law ought to be decided by larger Benches to ensure doctrinal consistency.

ST: I agree. The Supreme Court was never envisaged as a constitutional court alone. It was also designed to function as the country's final

> The pendency crisis cannot truly be addressed unless the Supreme Court develops a more robust mechanism to filter out frivolous litigation
>
> SWAPNIL TRIPATHI

court of appeal. Over time, however, its appellate jurisdiction has increasingly overshadowed its role in deciding constitutional questions. At the same time, the court must ensure that the inflow of routine appeals is reduced and that intervention is reserved for cases where it is genuinely warranted. I would, however, add an important caveat. Where courts are called upon to decide substantial questions of law, such matters ought ideally to be heard by larger Benches to minimise inconsistencies in interpretation among coordinate Benches.

Will increasing the Supreme Court's sanctioned strength lead to more conflicting rulings by coordinate Benches?

PR: Yes. An increase in the court's sanctioned strength is likely to result in greater doctrinal inconsistency, particularly when most judges sit in Division Benches of two. A larger number of Benches will inevitably result in a greater number of cases being entertained and, consequently, more conflicting rulings by coordinate Benches. Further, once divergent views emerge among coordinate Benches and matters require reference to larger Benches for authoritative resolution, delays are likely to become even more pronounced.

ST: I think the polyvocality of the Supreme Court is one of its strengths, but it works as a strength only when accompanied by judicial discipline. The two must complement each other. Judges may arrive at different conclusions on facts, but the application of legal principles must remain consistent.

Does the government need a more consistent litigation policy?

PR: The government was initially expected to introduce a National Litigation Policy (NLP) to reduce the overwhelming volume of cases involving the Union, State governments, and public sector undertakings that continue to clog the judicial system. The government eventually withdrew its assurance to introduce it, leaving unanswered questions about how decisions relating to government litigation are actually taken. There are numerous instances where similar cases remain pending before different High Courts, and instead of allowing at least one High Court to conclusively adjudicate the issue, the government files transfer petitions before the Supreme Court. The result is that these cases often remain pending before the top court for several more years.

ST: The government's litigation strategy often appears to be driven by a highly result-oriented, case-to-case approach rather than any coherent policy. Courts have repeatedly questioned why the government continues to pursue virtually every dispute up to the Supreme Court, even in cases where its position is clearly unsustainable. There is also a striking lack of institutional consistency. Changes in law officers often lead to shifts in legal strategy, with successive counsels sometimes advancing positions entirely contrary to those taken earlier. Ultimately, it is the individual litigant, lacking the State's resources and institutional capacity, who suffers the most.

What are the institutional reforms required?

ST: The pendency crisis cannot truly be addressed unless the Supreme Court develops a more robust mechanism to filter out frivolous litigation. This is particularly important in the context of Public Interest Litigations (PIL). The court must strictly apply the guidelines laid down in *State of Uttaranchal versus Balwant Singh Chaufal* (2010), including ensuring that a PIL is filed for a genuine public cause and not driven by personal or political interests. As for cases already pending before the court, stricter time allocation for oral arguments is essential. Greater reliance should also be placed on written submissions so that judicial time is not consumed by prolonged hearings.

Is this an opportunity to improve gender representation on the Bench?

PR: Yes. In my view, these four additional positions ought ideally to be filled by women. There must also be greater transparency in the appointments process.

ST: A common justification offered for not appointing more women judges is that there are not enough senior women judges in the High Courts. But the convention of seniority has often been relaxed when it comes to appointing male judges to the Supreme Court.

To listen to the full interview
Scan the code or go to the link
www.thehindu.com

Contradictions within India's cow protection regime

Faizan Mustafa

Vice-Chancellor, Chanakya National Law University, Patna, Bihar

Abdul Samad

Former Dean, Mumbai Veterinary College

The recent discovery of hundreds of cow carcasses at a dumping site in Jaisalmer, Rajasthan, rightly triggered an outrage on social media. A few years ago, a similar incident involving the mass starvation deaths of cows was reported from Chhattisgarh. The new Bharatiya Janata Party (BJP) government in West Bengal issued a public notice on May 13, 2026, laying down stringent conditions for the slaughter of animals under the West Bengal Animal Slaughter Control Act, 1950.

Last week, a two-judge Bench of the Calcutta High Court upheld the notice, observing that the conditions mentioned in the impugned order were issued in compliance with the High Court's order of August 16, 2018. Consequently, no cow, bull, bullock or even buffalo can be slaughtered without first obtaining a "certificate of fitness" from government officials. Despite all the rhetoric, the notification permitted the slaughter of cows older than 14 years, which justifiably annoyed Hindutva supporters.

Over 20 States in India have laws prohibiting cow slaughter. Only Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, Tripura, Manipur, Mizoram and Kerala do not have such laws. But what is the efficacy of these laws? Have the stringent provisions and enhanced punishments introduced over the last 12 years helped preserve cows, or could such laws ultimately contribute to their decline? Whether cow reverence constitutes an essential Hindu practice and whether such laws violate the right to privacy are issues that require a ruthlessly objective assessment.

Politics, faith and cows

Cow protection has long been a central Hindutva issue and which explains the contents of the Bengal notice. Yet, the Congress too has historically benefited from cow protection campaigns. Viceroy Lord Lansdowne famously observed that the cow protection movement had transformed the Indian National Congress from "a foolish debating society into a real political power". The cow and calf were the Congress's symbols for decades. Whenever the BJP comes to power in a State, amending cow slaughter prohibition laws to make them more stringent – by enhancing punishments, criminalising possession of beef, and restricting the transport of cattle within or outside the State – becomes a priority. The Gujarat law of 2017 even provides for life imprisonment, and in 2025, three persons were reportedly sentenced to this extreme punishment, ordinarily reserved for heinous offences such as murder, terrorist acts and dacoity. True, cow reverence among Hindus is ancient and enjoys near-unanimous acceptance, though scholars such as D.N. Jha have disputed this assertion citing scriptural material. He pointed to instances in *Dharmashastric* traditions where Yajnavalkya appears to endorse the consumption of beef, and highlighted the inconsistencies and polymorphic nature of Indian dietary practices. He also argued that the "holy" status accorded to the cow was largely a much later development, and noted that several prescriptive Hindu texts classified cow slaughter as a minor sin (*upapataka*) rather than a major offence (*mahapataka*). Strikingly, even the prominent Hindutva ideologue Vinayak Damodar Savarkar held views that differed significantly from those of many present-day Hindutva activists. Consequently, cow reverence may not satisfy the parameters of the essential religious practices test which requires practice to be mandatory from the time of origin of a religion.

Politics and sentiment continue to overshadow realities of cattle preservation in India

In *Mohd. Hanif Quareshi vs State of Bihar* (1958), the Supreme Court of India rightly held that cow slaughter on Bakr-Eid is not an essential Islamic practice either. Several Muslim rulers had also restricted cow slaughter. Babur advised Humayun to do so in his will, Jahangir's Edict No. 10 too prohibited animal slaughter on certain days out of respect for Hindu and Jain sentiments. The influential Deoband Islamic seminary too issued multiple fatwas discouraging cow slaughter. Even in the Constituent Assembly debates on November 24, 1948, Muslim members such as Z.H. Lari and Mohammad Saadullah insisted that "it is better to come forward and incorporate a clause in fundamental rights that cow slaughter is henceforth prohibited, rather than it being left vague in the directive principles…."

What cattle census data reveal

Dr. B.R. Ambedkar eventually placed cow protection within the non-justiciable Directive Principles under Article 48 of the Constitution, following which several States enacted laws after Independence prohibiting cow slaughter. Yet, cattle census data suggest that the objective of preserving and increasing the cow population has not been achieved. West Bengal, for instance, was among the few States where culling and sale of cows and bulls were not entirely prohibited. By conventional logic, its cow population should therefore have been far lower than that of States such as Gujarat, Uttar Pradesh and Maharashtra. However, since 1951, the cow population in the country has grown by only 49.63%, while the buffalo population has risen by 153.8% and the female buffalo population by 161.9%. The figures speak for themselves: cows face the risk of decline.

Ironically, the unprotected buffalo population has grown far more rapidly, especially in the so-called cow-belt States. A comparison of cattle growth rates shows that West Bengal, despite lacking stringent cow slaughter laws, has performed better than States with strict prohibitions. Even though male cattle are protected in these States, their population has declined sharply – by 38.3% in Gujarat, 31.4% in Maharashtra and 58.27% in Uttar Pradesh. In contrast, the decline in male cattle population in West Bengal was only 22.8%. The data also suggest that stringent prohibition laws may be pushing farmers in these States towards buffalo rearing, reflected in the declining cattle-to-buffalo ratio between 2012 and 2019. In West Bengal, by contrast, buffaloes remain insignificant in number and their population sharply declined in 2019. In 1997, the cattle to buffalo ratio was 144:1 but in 2019 it became 295:10. In Uttar Pradesh, the cattle-to-buffalo ratio fell from 105:100 in 1997 to 56:100 in 2019. West Bengal, despite lacking stringent prohibitions, witnessed a comparatively stronger growth in cow population and, therefore, mere laws will not protect cows.

Cattle populations grow in a compounded manner because, unlike humans, a cow gives birth to its first calf at around three years and, to remain productive, must calve every 14-16 months. Calves born during a census period also mature and begin reproducing within a few years. According to growth forecasting models, if no cattle were culled or slaughtered and all calves survived except for natural deaths, the cattle population would increase by 2.5 to three times within five years – something that has never occurred in any State. Such growth is economically unsustainable, as farmers cannot support such numbers due to fodder scarcity.

Undermining the farmer

When farmers are legally allowed to exercise their judgment in culling unproductive cattle, they earn additional income to meet expenses such as weddings, children's education and health care. According to simulation models, farmers in West Bengal earned nearly ₹35,000 crore between 2012 and 2019 from the lawful sale of cattle for slaughter, apart from their dairy income. Farmers in States with strict prohibition laws also appear to have sold cattle for slaughter as is reflected in declining cattle populations, but likely to have earned far less because of the illegality of such sales and the possibility of bribery and middlemen. In effect, these laws do not penalise butchers or beef consumers, but farmers themselves. West Bengal appears to have recognised this reality with Muslim refusal to purchase cows for Eid slaughter. In India's agrosilvopastoral economy, livestock remains a vital component of rural livelihoods.

In the privacy judgment of *K.S. Puttaswamy* (2017), Justice J. Chelameswar had observed "I do not think that anybody would like to be told by the State as to what they should eat or how they should dress or whom they should be associated with either in their personal, social or political life." Justice Chandrachud said that what one eats is one's personal affair and it is a part of privacy under Article 21, i.e., right to life and personal liberty In view of the politicisation of the issue, Muslims in Bengal prudently refrained from cow slaughter during Eid. One hopes that this will promote social harmony and counter communal hate campaigns. Maulana Arshad Madani, president of the Jamiat Ulama-e-Hind (Arshad Madani faction), has also called for the cow to be declared the national animal. The first writer of this article, though not a veterinary expert, believes that Muslims across India should support a central law banning cow slaughter and imposing stringent punishment, especially on those who sell cows for slaughter.

The views expressed are personal

SC sets aside ₹202-cr. penalty on Amazon in Future Coupons case

Apex court rescinds Competition Commission of India order revoking Amazon's buy-in of 49% stake in Future Coupons in a 2019 combination

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

Rule of law: The Supreme Court said that the Competition Act, 2002 "promotes as well as protects". REUTERS

The Supreme Court has set aside a Competition Commission of India (CCI) order revoking Amazon's buy-in of 49% stake in Future Coupons in a 2019 combination. The court also rescinded a ₹202-crore penalty on Amazon by the competition regulator.

A Bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta, in a judgment, held that enforcement by the regulator must protect competition without undermining market confidence.

It said the regulator's interventions to promote market competition must not be compromised by unpredictability or form-driven approaches that did not serve the statutory purpose of the Competition Act, 2002.

The top court said fair treatment of foreign investors did not mean special treatment. "It means equal treatment under the same law, administered through the same procedural safeguards and disciplined reasoning," Justice Nath, who authored the May 27 judgment, said.

Amazon's 2019 investment of ₹1,431 crore in Future Coupons, which would give it indirect sway over Future Retail, went sour when the Future Group tried to sell its retail assets to Reliance Retail in 2020. Amazon had challenged the move, only to have the CCI suspend its initial approval of the 2019 deal while fining Amazon ₹202 crore on the grounds of "suppression, omission, and misrepresentation" of its perceived larger interests in Future Retail.

The court concluded that the CCI acted outside the statutory authority by withdrawing the approval given to the Amazon-Future Coupons combination in 2019. It said that the CCI had all the "contemporaneous regulatory record", executed agreements, and connected arrangements while granting approval.

"It was on that record that the CCI undertook scrutiny and granted approval under Section 31(1) of the Act. In these circumstances, a later and more formal view of how the same material ought to have been described cannot convert an approved filing into a case of non-notification or suppression in substance," the apex court said.

The court said the Competition Act, a "forward-looking instrument of economic regulation", and the CCI play key roles in preserving and regulating competitive markets in India. The court said the 2002 Act "promotes as well as protects".

"The Act is enacted, keeping in view the economic development of the country, to prevent practices having adverse effect on competition, to promote and sustain competition, to protect the interests of consumers, and to ensure freedom of trade carried on by other participants in markets in India," the court said.